

## राजस्थान उच्च न्यायालय

## जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2602/2024

सावित्री शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ शर्मा पत्नी श्री अरुण प्रसाद, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी 90 ए, शंकर नगर, जयदुर्गा स्कूल के पास, माउंट रोड, थाना ब्रह्मपुरी, जयपुर शहर-302002

----याचिकाकर्ता

## बनाम

- भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, वरिष्ठ अधीक्षक (नीति) के माध्यम से, जी-14, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना इंगरी, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए

:

श्री राकेश चंदेल

श्री अभिनव भंडारी

प्रतिवादी के लिए

:

सुश्री मनजीत कौर

## न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश14/11/2024

रिपोर्ट करने योग्य:-

- इस रिट याचिका को दायर करके, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने के निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता एक भारतीय नागरिक है और उसके पास पासपोर्ट संख्या K3335738 था, जो उसे 17.05.2012 को

जारी किया गया था और यह 16.05.2022 तक वैध था। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि जब याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो प्रतिवादियों द्वारा उसका नवीनीकरण नहीं किया गया और उक्त आवेदन को बिना किसी उचित कारण बताए लिखित रूप में अस्वीकार कर दिया गया, अतः इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और निवेदन किया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली ने इस संबंध में पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी और पुलिस द्वारा 07.08.2022 को एक प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह टिप्पणी की गई थी, "फोटो समान, राष्ट्रीयता संदिग्ध (नेपाली) आवेदक के लिखित बयान के अनुसार"। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि पुलिस सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता की पहचान विवादित थी, अतः इस परिस्थिति में, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया है।

4. बहस के दौरान किए गए निवेदनों को सुना और उन पर विचार किया गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

5. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादियों द्वारा जारी किया गया एक वैध पासपोर्ट संख्या K3335738 था और यह 17.05.2012 से 16.05.2022 तक वैध था।

6. जब उक्त पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई, तो याचिकाकर्ता ने उसके नवीनीकरण के लिए प्रतिवादी-प्राधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इस बार प्रतिवादी-प्राधिकारियों द्वारा प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर एक तकनीकी आपत्ति उठाई गई और पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया गया। प्रतिवादियों द्वारा नवीनीकरण न करने का कारण याचिकाकर्ता की राष्ट्रीयता के बारे में था और प्रतिवादियों द्वारा इसे विवादित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।

7. स्पष्ट रूप से, प्रतिवादियों द्वारा रिकॉर्ड पर कोई ऐसी सामग्री नहीं रखी गई है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक नहीं है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि उसका जन्म 05.05.1990 को दिल्ली के तिहाड़ कॉम्प्लेक्स स्थित केंद्रीय

जेल में हुआ था और उप-रजिस्ट्रार, मृत्यु और जन्म नगर निगम, दिल्ली ने याचिकाकर्ता का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में 'सीबीएसई') से उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की और आयकर विभाग द्वारा उसे स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड जारी किया गया है। सक्षम प्राधिकारियों ने उसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है। याचिकाकर्ता का विवाह 23.11.2017 को अरुण प्रसाद के साथ संपन्न हुआ था और उसका विवाह पंजीकृत है तथा विवाह पंजीकरण अधिकारी, जयपुर द्वारा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। याचिकाकर्ता के पति और पिता दोनों भारत के स्थायी निवासी हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 (1)(b) के आधार पर इस देश की नागरिकता प्राप्त की है। रिट याचिका के साथ संलग्न विभिन्न दस्तावेज इंगित करते हैं कि वे भारतीय नागरिक हैं और प्रतिवादी कोई भी ऐसी सामग्री दिखाने में असमर्थ रहे हैं, जो उपरोक्त तथ्य पर दूर से भी संदेह पैदा कर सके।

8. आगे बढ़ने से पहले नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 और धारा 9 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार हैं:-

"3. जन्म से नागरिकता- (1) उप-धारा (2) में यथाउपबंधित के सिवाय, भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति,-

(क) 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई, 1987 से पहले;

(ख) 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद, किंतु नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से पहले और जिसके माता-पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है;

(ग) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ को या उसके बाद, जहां-

(i) उसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं; या  
(ii) उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है।

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म के समय-

(क) उसके पिता या माता के पास ऐसे वाद और विधिक प्रक्रिया से ऐसी उन्मुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को मान्यता प्राप्त किसी विदेशी संप्रभु शक्ति के दूत को प्रदान की जाती है और वह, जैसा भी मामला हो, भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) उसके पिता या माता शत्रु विदेशी हैं और जन्म उस स्थान पर होता है जो उस समय शत्रु के कब्जे में था।

9. नागरिकता का समापन- (1) भारत का कोई भी नागरिक जो देशीयकरण, पंजीकरण या अन्यथा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, या जिसने 26 जनवरी, 1950 और इस अधिनियम के प्रारंभ के बीच किसी भी समय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, ऐसी प्राप्ति पर या, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रारंभ पर, भारत का नागरिक नहीं रहेगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी भारत के ऐसे नागरिक पर लागू नहीं होगा, जो किसी ऐसे युद्ध के दौरान जिसमें भारत संलग्न हो सकता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या, कब या कैसे किसी [भारत के नागरिक] ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, तो इसका निर्धारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसे तरीके से, और साक्ष्य के ऐसे नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जैसा इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।"

9. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3(1)(b) के सीधे पढ़ने से यह स्पष्ट है कि भारत में 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद, किंतु नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से पहले जन्मा प्रत्येक व्यक्ति और जिसके माता-पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है, जन्म से नागरिकता प्राप्त करेगा। एकमात्र अपवाद उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित है। ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति के माता-पिता में से किसी एक के पास वाद और विधिक प्रक्रिया से ऐसी उन्मुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को मान्यता प्राप्त किसी विदेशी संप्रभु शक्ति के दूत को प्रदान की जाती है और उक्त माता-पिता भारत का नागरिक नहीं है, तो भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं करेगा। दूसरा अपवाद उस मामले में है जहां व्यक्ति के माता-पिता में से कोई एक शत्रु विदेशी है और जन्म उस स्थान पर होता है जो उस समय शत्रु के कब्जे में था। स्पष्ट रूप से, इन दोनों में से कोई भी अपवाद इस मामले में लागू नहीं होता है।

10. याचिकाकर्ता न तो "नेपाली" है और न ही उसके पास इस संबंध में कोई दस्तावेज है और ऐसा कोई भी सामग्री नहीं है जो याचिकाकर्ता की नागरिकता पर कोई संदेह पैदा करे।

11. यह न्यायालय याचिकाकर्ता के जन्म का अधिवास को अनदेखा नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता का जन्म भारत में हुआ था और उसका जन्म का अधिवास भारत है। जन्म का अधिवास कानून की एक अवधारणा है और यह किसी व्यक्ति से तब तक जुड़ा रहता है जब तक वह पसंद का अधिवास प्राप्त करके इसे त्याग नहीं देता। याचिकाकर्ता का जन्म भारत में हुआ था और उसका जन्म का अधिवास भारत है और जब उसके पिता और पति भारत के स्थायी नागरिक हैं, तो प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्ति, जिसमें "फोटो समान राष्ट्रीयता संदिग्ध (नेपाली)" टिप्पणी की गई है, कानून की दृष्टि में अस्थिर है।

12. यदि प्रतिवादियों का यह मामला होता कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक नहीं है, तो निश्चित रूप से प्रतिवादियों को वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी नहीं करना चाहिए था। प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्ति का कोई आधार नहीं है, अतः इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के पासपोर्ट का नवीनीकरण न करने का प्रतिवादियों का कार्य न्यायोचित नहीं है।

13. भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा करने का एक मौलिक अधिकार है और उसे ऐसे आधारों पर पासपोर्ट जारी करने से मना नहीं किया जा सकता है जो कानून की दृष्टि में अस्थिर हैं। तथ्यात्मक रूप से, विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट एक आवश्यक शर्त है और पासपोर्ट को रोककर, सरकार उसे उसके अधिकार से प्रभावी ढंग से वंचित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में, अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी राज्य/केंद्र सरकार किसी विदेशी को वैध पासपोर्ट के बिना अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है।

14. सतवंत सिंह साहनी बनाम डी. रामारत्नम और अन्य में, जो 1967 (3) एससीआर 525 में रिपोर्ट किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने पासपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डाला है क्योंकि भारत में रहने वाले व्यक्ति के लिए वैध पासपोर्ट के बिना विदेशी देशों की यात्रा करना या वापस लौटना कभी संभव नहीं है। पैराग्राफ 7 इस प्रकार है:

"7. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रों के बीच प्रचलन के परिणामस्वरूप, भारत में रहने वाले व्यक्ति के लिए, कुछ अपवादों को छोड़कर, पासपोर्ट के बिना विदेशी देशों की यात्रा करना संभव नहीं है। भारत सरकार ने शिपिंग और एयरलाइन कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे भारत छोड़ने वाले यात्रियों को तब तक बोर्ड पर न लें जब तक उनके पास वैध पासपोर्ट न हो। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1920 की धारा 8 के तहत, केंद्र सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिनके लिए यह आवश्यक हो कि भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के पास पासपोर्ट हो। उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए गए थे। उसके नियम 3 के तहत, भारत के बाहर किसी भी स्थान से आने वाला कोई भी व्यक्ति जल, भूमि या वायु द्वारा भारत में प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि उसके पास नियम 4 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप एक वैध पासपोर्ट न हो। उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्धारित रैंक से कम के पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है; और नियमों के नियम 6 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो उक्त नियमों का उल्लंघन करता है, उसे 3 महीने तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत से हटाने का निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का संयुक्त प्रभाव यह है कि केंद्र सरकार द्वारा शिपिंग और एयरलाइन कंपनियों को दिए गए कार्यकारी निर्देश और विदेशी देशों द्वारा पासपोर्ट के कब्जे पर जोर देना, इससे पहले कि किसी भारतीय को उन देशों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, यह स्पष्ट करता है कि पासपोर्ट का कब्जा, चाहे उसका अर्थ या कानूनी प्रभाव कुछ भी हो, विदेश यात्रा के लिए भारत छोड़ने के लिए एक आवश्यक शर्त है। यह तर्क कि अधिनियम भारत से बाहर निकलने की शर्त के रूप में पासपोर्ट लेने को अनिवार्य नहीं करता है, इसलिए यह किसी व्यक्ति के भारत छोड़ने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है, यदि हम ऐसा कहें, तो यह बल्कि अति-तकनीकी है और स्थिति की वास्तविकताओं को अनदेखा करता है। इस तथ्य के अलावा कि पासपोर्ट का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यात्रा की एक आवश्यक शर्त है, प्रवेश के खिलाफ निषेध परोक्ष रूप से व्यक्ति को भारत छोड़ने से रोकता है। राज्य वास्तव में भारत में रहने वाले व्यक्ति से कहता है "आप अपनी इच्छा से बिना पासपोर्ट के भारत छोड़ सकते हैं, लेकिन विदेशी देश आपको इसके बिना उनमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे और आप इसके बिना भारत वापस

भी नहीं आ सकते।" भारत में कोई भी व्यक्ति उन शर्तों पर यात्रा नहीं कर सकता है। वास्तव में उसके लिए ऐसा करना असंभव है। इसके अलावा, बाहर निकलने की वह सैद्धांतिक संभावना भी कार्यकारी निर्देशों और विदेशी मुद्रा से इनकार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। इसलिए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक भारतीय पासपोर्ट वास्तव में विदेश यात्रा के लिए एक आवश्यक शर्त है और इसके बिना भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर यात्रा नहीं कर सकता है।"

15. इसी तरह, निर्णय के पैराग्राफ 12 और 13 में नागरिकों के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें इस प्रकार भी पुनरुत्पादित किया जा सकता है:

"12. पासपोर्ट की अनुपस्थिति वास्तव में किसी व्यक्ति को भारत छोड़ने से रोकती है। चाहे हम इसे विदेश यात्रा के लिए किसी व्यक्ति को दी गई सुविधा के रूप में देखें या किसी विदेशी देश से धारक को राजनयिक संरक्षण देने के अनुरोध के रूप में, यह नकारा नहीं जा सकता कि भारत सरकार, भारत में रहने वाले व्यक्ति को परमिट देने से इनकार करके, उसे विदेश यात्रा करने से पूरी तरह से रोकती है। यदि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या नहीं, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, तो सरकार पासपोर्ट रोककर उसे उसके अधिकार से वंचित कर सकती है। इसलिए, इन रिट याचिकाओं में वास्तविक प्रश्न यह है: क्या भारत में रहने वाले व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का मौलिक अधिकार है?"

13. संविधान का प्रासंगिक अनुच्छेद अनुच्छेद 21 है। यह पढ़ता है: "अनुच्छेद 21. किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।" यदि यात्रा करने का अधिकार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, तो उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस न्यायालय ने गोपालन के मामले, MANU/SC/0012/1950: 1950CriLJ1383 में माना है कि उस अनुच्छेद में 'विधि' का अर्थ अधिनियमित विधि है और यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य ने किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को वंचित करने या विनियमित करने के लिए कोई विधि नहीं बनाई है।"

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में, जो 1978 एससीआर 621 में रिपोर्ट किया गया है, कानून को आगे स्पष्ट किया गया है, जिसमें पैरा 3 में इस प्रकार कहा गया है:

"3. इससे पहले कि हम इस याचिका में उठने वाले विभिन्न प्रश्नों के संबंध में पक्षों की ओर से दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करें, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना सुविधाजनक होगा। यह अधिनियम 24 जून, 1967 को इस न्यायालय के सतवंत सिंह साहनी बनाम डी. रामारत्नम, सहायक पासपोर्ट अधिकारी, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्णय के मद्देनजर अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने से पहले की स्थिति यह थी कि भारत के तटों को छोड़कर विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने को विनियमित करने वाला कोई कानून नहीं था। पासपोर्ट जारी करना पूरी तरह से कार्यपालिका के विवेक पर था और यह विवेक अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट था। इस न्यायालय ने, बहुमत से, यह माना कि अनुच्छेद 21 में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति में आवागमन और विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है और अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विदेश जाने के उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है। चूंकि राज्य द्वारा ऐसे अधिकार के प्रयोग को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं बनाया गया था, इसलिए पासपोर्ट से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था। इसके अलावा, पासपोर्ट जारी करने या इनकार करने के मामले में कार्यपालिका का विवेक अनियंत्रित और मनमाना होने के कारण, यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था और इसलिए याचिकाकर्ता को पासपोर्ट से इनकार करने का आदेश भी उस अनुच्छेद के तहत अमान्य था। इस निर्णय को संसद ने स्वीकार कर लिया और इसके द्वारा इंगित दोष को पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अधिनियमन द्वारा ठीक कर दिया गया। यह अधिनियम, जैसा कि इसकी प्रस्तावना दर्शाती है, पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने, भारत के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के भारत से प्रस्थान को विनियमित करने और आकस्मिक और सहायक मामलों के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा 3 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति भारत से प्रस्थान नहीं करेगा या प्रस्थान करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि उसके पास इस संबंध में एक वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज न हो। अधिनियम के तहत जारी किए जा सकने वाले पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के विभिन्न वर्ग धारा 4 में निर्धारित किए गए हैं। धारा 5 की उप-धारा (1) में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने या ऐसे पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर विदेशी देश या देशों की यात्रा के लिए पृष्ठांकन के लिए आवेदन करने का प्रावधान है और उप-धारा (2) कहती है कि ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, पासपोर्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, लिखित



आदेश द्वारा, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करेगा या जारी करने से इनकार करेगा या आवेदन में निर्दिष्ट एक या अधिक विदेशी देशों के संबंध में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर पृष्ठांकन करेगा या करने से इनकार करेगा। उप-धारा (3) में पासपोर्ट प्राधिकारी को, जहां वह पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने या पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर कोई पृष्ठांकन करने से इनकार करता है, ऐसे आदेश को करने के अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है। धारा 6 की उप-धारा (1) उन आधारों को निर्धारित करती है जिन पर पासपोर्ट प्राधिकारी किसी विदेशी देश की यात्रा के लिए पृष्ठांकन करने से इनकार करेगा और प्रावधान करती है कि किसी अन्य आधार पर पृष्ठांकन से इनकार नहीं किया जाएगा। इस उप-धारा में चार आधार निर्धारित किए गए हैं और उनमें से अंतिम यह है कि, केंद्र सरकार की राय में, ऐसे विदेशी देश में आवेदक की उपस्थिति सार्वजनिक हित में नहीं है। इसी तरह धारा 6 की उप-धारा (2) उन आधारों को निर्दिष्ट करती है जिन पर अकेले - और किसी अन्य आधार पर नहीं - पासपोर्ट प्राधिकारी किसी विदेशी देश की यात्रा के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार करेगा और वहां निर्धारित विभिन्न आधारों में से अंतिम यह है कि, केंद्र सरकार की राय में, आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। फिर हम धारा 10 पर आते हैं जो विचार के लिए महत्वपूर्ण धारा है। उस धारा की उप-धारा (1) पासपोर्ट प्राधिकारी को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के पृष्ठांकन को बदलने या रद्द करने या उन शर्तों को बदलने या रद्द करने का अधिकार देती है जिनके अधीन एक पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किया गया है, अन्य बातों के अलावा, धारा 6 की उप-धारा (1) या धारा 19 के तहत किसी अधिसूचना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। उप-धारा (2) पासपोर्ट प्राधिकारी को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक के आवेदन पर और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की शर्तों को बदलने या रद्द करने की शक्तियां प्रदान करती है। उप-धारा (3) में प्रावधान है कि पासपोर्ट प्राधिकारी खंड (क) से (ज) में निर्धारित आधारों पर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त कर सकता है या जब्त करवा सकता है या रद्द कर सकता है। इस मामले में पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश केंद्र सरकार द्वारा खंड (ग) के तहत किया गया था जो इस प्रकार पढ़ता है: (ग) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के किसी भी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, या सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है; आदेश करने के लिए जिस विशेष आधार पर भरोसा किया गया था, वह खंड (ग) के अंतिम

भाग में निर्धारित किया गया था, अर्थात्, केंद्र सरकार पासपोर्ट को "सामान्य जनता के हित में" जब्त करना आवश्यक समझती है। फिर उप-धारा (5) आती है जिसमें पासपोर्ट प्राधिकारी को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त करने या रद्द करने या उस पर किए गए पृष्ठांकन को बदलने या रद्द करने के लिए "ऐसे आदेश को करने के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करने और पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक को मांग पर उसकी एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता है, जब तक कि, किसी भी मामले में, पासपोर्ट प्राधिकारी की राय में, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के किसी भी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सामान्य जनता के हित में ऐसी प्रति प्रदान करना हित में नहीं होगा"। इस उप-धारा के बाद के भाग में निहित प्रावधान के आधार पर ही केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने के कारणों के विवरण की एक प्रति प्रदान करने से इनकार कर दिया था, इस आधार पर कि ऐसी प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान करना सामान्य जनता के हित में नहीं था। यह वास्तव में खेद का विषय है कि केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता के कारणों के विवरण की एक प्रति प्रदान करने के अनुरोध के जवाब में यह रुख अपनाया था, क्योंकि अंततः, जब याचिका दायर की गई, तो केंद्र सरकार ने याचिका के जवाब में हलफनामे में कारणों का खुलासा किया, जिससे पता चलता है कि यह वास्तव में सार्वजनिक हित के विपरीत नहीं था और यदि हम जवाब में हलफनामे में दिए गए कारणों को देखें, तो यह स्पष्ट होगा कि कोई भी उचित व्यक्ति यह विचार नहीं कर सकता था कि कारणों के प्रकटीकरण से सामान्य जनता के हितों को नुकसान होगा। यह एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि कैसे एक सांविधिक प्राधिकारी को सामान्य जनता के हितों में कार्य करने के लिए प्रदत्त शक्ति का कभी-कभी अनुचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर नहीं की होती, तो शायद वह कभी यह पता नहीं लगा पाती कि उसके पासपोर्ट को जब्त करने और उसे विदेश जाने के अधिकार से वंचित करने के क्या कारण थे। कारणों को देने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से उप-धारा (5) में इसलिए शुरू की गई है ताकि यह शक्ति के दुरुपयोग या गलत उपयोग के खिलाफ एक स्वस्थ जांच के रूप में कार्य कर सके। यदि दिए गए कारण प्रासंगिक नहीं हैं और कारणों और उस आधार के बीच कोई संबंध नहीं है जिस पर पासपोर्ट जब्त किया गया है, तो पासपोर्ट के धारक के लिए इसे जब्त करने के आदेश को कानून की अदालत में चुनौती देना खुला होगा और यदि अदालत संतुष्ट है कि कारण बाहरी या अप्रासंगिक हैं, तो अदालत आदेश को रद्द कर देगी। न्यायिक जांच के संपर्क में आने की यह देयता स्वयं शक्ति के अनुचित या दुर्भावनापूर्ण

प्रयोग के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करेगी। इसलिए, अदालत पासपोर्ट प्राधिकारी के इस दावे को बिना गहन जांच के स्वीकार करने में बहुत धीमी होगी कि कारणों का खुलासा करना सामान्य जनता के हितों में नहीं होगा। पासपोर्ट प्राधिकारी को उचित सामग्री रखकर अदालत को संतुष्ट करना होगा कि कारणों को देना स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से सामान्य जनता के हितों के खिलाफ होगा और यदि अदालत संतुष्ट नहीं है, तो अदालत पासपोर्ट प्राधिकारी को कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता कर सकती है, सरकार की ओर से स्थापित किए जा सकने वाले किसी भी वैध और कानूनी विशेषाधिकार के दावे के अधीन। यहां वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, केंद्र सरकार ने शुरू में दावा किया था कि पासपोर्ट को जब्त करने के कारणों का खुलासा करना सामान्य जनता के हितों के खिलाफ होगा, लेकिन जब जवाब में हलफनामा दायर करने की बात आई, तो केंद्र सरकार ने बहुत ही उचित रूप से इस कानून की दृष्टि में अस्थिर दावे को छोड़ दिया और कारणों का खुलासा किया। यह प्रश्न कि क्या इन कारणों का सामान्य जनता के हितों से कोई संबंध है या वे बाहरी और अप्रासंगिक हैं, एक ऐसा मामला है जिसकी हम जांच करेंगे जब हम पक्षों के तर्कों से निपटेंगे। इस बीच, प्रासंगिक प्रावधानों के सारांश के साथ आगे बढ़ते हुए, धारा 11 का संदर्भ दिया जा सकता है जो धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त करने या रद्द करने के आदेश के खिलाफ अन्य बातों के अलावा अपील का प्रावधान करती है। लेकिन इस धारा में एक परंतुक है जो कहता है कि यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त करने या रद्द करने का आदेश केंद्र सरकार द्वारा पारित किया जाता है, तो अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। ये अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान हैं जिनके आलोक में हमें धारा 10 की उप-धारा (3)(ग) की संवैधानिकता और याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश की वैधता पर विचार करना है।"

17. अधिनियम की धारा 10(3)(c) के तहत पारित आदेश की संवैधानिक आवश्यकता पर पैराग्राफ 35 में आगे विचार किया गया है जिसे नीचे संदर्भित किया जा सकता है:

"35. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 10(3)(c) के तहत किया गया आदेश अनुच्छेद 19(1)(a) या (g) का उल्लंघन नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने वाले चुनौतीप्राप्त आदेश की संवैधानिक वैधता पर चर्चा करते हुए, हमें यह इंगित करने का अवसर मिलेगा कि जहां किसी प्राधिकारी को कार्रवाई करने का अधिकार देने वाला सांविधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध है, वहां उसके तहत की गई कार्रवाई एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकती है और उस स्थिति में,

यद्यपि सांविधिक प्रावधान वैध है, कार्रवाई शून्य हो सकती है। इसलिए, भले ही धारा 10(3)(c) वैध हो, यह प्रश्न हमेशा बना रहेगा कि क्या इसके तहत किया गया आदेश मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के कारण अमान्य है। पासपोर्ट जब्त करने के आदेश का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव, किसी दिए गए मामले में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी पेशे को करने के अधिकार को कम करना या छीनना हो सकता है और जहां ऐसा मामला है, आदेश अमान्य होगा, जब तक कि अनुच्छेद 19(2) या अनुच्छेद 19(6) द्वारा इसे बचाया न जाए। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय उड़ान लाइसेंस वाला एक पायलट। अंतरराष्ट्रीय उड़ान उसका पेशा है और यदि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, तो यह उसके पेशे को करने के अधिकार में सीधे हस्तक्षेप करेगा और जब तक आदेश को अनुच्छेद 19(6) के तहत सार्वजनिक हित के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, तब तक यह अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करने के कारण शून्य होगा। एक और उदाहरण एक प्रचारक का लिया जा सकता है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपने विश्वास का प्रचार करना अपने जीवन का मिशन बना लिया है और उस उद्देश्य के लिए, विभिन्न देशों में संस्थान स्थापित करता है। यदि उसका पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया जाता है, तो यह उसकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित करेगा और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आदेश की वैधता को चुनौती अनुत्तरित होगी जब तक कि इसे अनुच्छेद 19(2) द्वारा बचाया न जाए। हमने ये दो उदाहरण केवल दृष्टांत के रूप में लिए हैं। ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां लगाया गया प्रतिबंध स्पष्ट रूप से केवल विदेश जाने के अधिकार पर है लेकिन प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी पेशे को करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना है। एक संगीतकार गाने के लिए विदेश जाना चाह सकता है, एक नर्तक नृत्य करने के लिए, एक अतिथि प्रोफेसर पढ़ाने के लिए और एक विद्वान एक सम्मेलन या संगोष्ठी में भाग लेने के लिए। यदि ऐसे मामले में उसका पासपोर्ट अस्वीकृत या जब्त कर लिया जाता है, तो यह उसकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सीधे हस्तक्षेप करेगा। यदि किसी समाचार पत्र के संवाददाता को विदेशी असाइनमेंट दिया जाता है और उसे पासपोर्ट से इनकार कर दिया जाता है या उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, तो यह उसके पेशे को करने की स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप होगा। उदाहरणों को गुणा किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि यद्यपि विदेश जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, विदेश जाने के अधिकार से इनकार, वास्तव में और प्रभाव में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी पेशे को करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है

ताकि अनुच्छेद 19(1)(a) या 19(1)(g) का उल्लंघन हो। ऐसे मामले में, पासपोर्ट से इनकार या जब्त करना अमान्य होगा जब तक कि इसे अनुच्छेद 19(2) या अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित नहीं ठहराया जाता है, जैसा भी मामला हो। अब, पासपोर्ट को धारा 10(3)(e) के तहत जब्त किया जा सकता है यदि पासपोर्ट प्राधिकारी इसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के किसी भी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में या सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है। पहली तीन श्रेणियां अनुच्छेद 19(2) के समान हैं और उनमें से प्रत्येक, हालांकि अलग से उल्लिखित है, "सामान्य जनता के हित" के व्यापक वर्ग के भीतर एक प्रजाति है। अभिव्यक्ति "सामान्य जनता के हित" एक व्यापक अभिव्यक्ति है जो अपने व्यापक दायरे में सामान्य जनता के सभी प्रकार के हितों को शामिल करती है जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित शामिल हैं। इसलिए, जब धारा 10(3)(c) के तहत एक आदेश दिया जाता है, जो उस प्रावधान के नियमों के अनुरूप है, तो यह सामान्य जनता के हित में होगा और भले ही यह किसी पेशे को करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता हो, यह अनुच्छेद 19(6) द्वारा संरक्षित होगा। लेकिन यदि धारा 10(3)(c) के तहत किया गया आदेश भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, तो यह पर्याप्त नहीं होगा कि यह सामान्य जनता के हित में किया गया है। उस अनुच्छेद का संरक्षण प्राप्त करने के लिए इसे अनुच्छेद 19(2) के नियमों के भीतर आना चाहिए। यदि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में या भारत की सुरक्षा के हित में या भारत के किसी भी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 19(2) की आवश्यकता को पूरा करेगा। लेकिन यदि यह "सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता" के हितों को छोड़कर सामान्य जनता के किसी अन्य हित के लिए किया जाता है, तो इसे अनुच्छेद 19(2) का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित "सामान्य जनता के हित" हैं और वे धारा 10(3)(c) द्वारा कवर किए जाएंगे, लेकिन अभिव्यक्ति "सामान्य जनता के हित", जैसा कि पहले ही बताया गया है, एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है और, इसलिए, धारा 10(3)(c) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला एक आदेश, अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन न करे, इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे आदेश के संबंध में, धारा 10(3)(c) में अभिव्यक्ति "सामान्य जनता के हित" को सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों तक सीमित करने के लिए व्याख्या को सीमित करना

चाहिए। यदि धारा 10(3)(c) के तहत किया गया आदेश भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, तो इसे व्यापक अर्थों में सामान्य जनता के हित में नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में किया जाना चाहिए, अन्य तीन श्रेणियों, अर्थात्, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित, भारत की सुरक्षा और भारत के किसी भी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के अलावा। यदि आदेश को सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में नहीं दिखाया जा सकता है, तो यह न केवल अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करेगा, बल्कि धारा 10(3)(c) द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से भी बाहर होगा।"

18. अब इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि "क्या प्रतिवादी प्रतिकूल पुलिस सत्यापन के आधार पर याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार कर सकते हैं?" पासपोर्ट से केवल पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (संक्षेप में "1967 का अधिनियम") की धारा 6 में उल्लिखित आधारों पर ही इनकार किया जा सकता है। 1967 के अधिनियम की धारा 5 पासपोर्ट और हार्ड दस्तावेजों आदि के जारी करने से संबंधित है। यह इस प्रकार है:-

"5. पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेजों आदि के लिए आवेदन, और उन पर आदेश।- (1) इस अधिनियम के तहत ऐसे विदेशी देश या देशों (एक नामित विदेशी देश नहीं) का दौरा करने के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन, जैसा कि आवेदन में निर्दिष्ट किया जा सकता है, पासपोर्ट प्राधिकारी को किया जा सकता है और इसके साथ 2 [विशेष सुरक्षा कागज, मुद्रण, लेमिनेशन और पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज जारी करने में अन्य संबंधित विविध सेवाओं पर किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित शुल्क] होगा।

(1A) जारी करने के लिए एक आवेदन-

(i) इस अधिनियम के तहत एक नामित विदेशी देश का दौरा करने के लिए एक पासपोर्ट; या

(ii) इस अधिनियम के तहत एक यात्रा दस्तावेज, ऐसे विदेशी देश या देशों (एक नामित विदेशी देश सहित) का दौरा करने के लिए जैसा कि आवेदन में निर्दिष्ट किया जा सकता है या इस धारा में संदर्भित पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर एक पृष्ठांकन के लिए, पासपोर्ट प्राधिकारी को किया जा सकता है और इसके साथ ऐसा शुल्क (यदि कोई हो) पचास रुपये से अधिक नहीं होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(1B) इस धारा के तहत प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसे विवरण होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) [इस धारा के तहत] एक आवेदन प्राप्त होने पर, पासपोर्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, लिखित आदेश द्वारा, -

(क) विदेशी देश या देशों के संबंध में, जैसा कि आवेदन में निर्दिष्ट है, पृष्ठांकन के साथ पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करेगा, या, जैसा भी मामला हो, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर पृष्ठांकन करेगा; या

(ख) आवेदन में निर्दिष्ट एक या अधिक विदेशी देशों के संबंध में पृष्ठांकन के साथ पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करेगा, या, जैसा भी मामला हो, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर पृष्ठांकन करेगा और अन्य देश या देशों के संबंध में पृष्ठांकन करने से इनकार करेगा; या

(ग) पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार करेगा, या, जैसा भी मामला हो, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर कोई पृष्ठांकन करने से इनकार करेगा।

(3) जहां पासपोर्ट प्राधिकारी किसी व्यक्ति के आवेदन पर उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत एक आदेश देता है, तो वह ऐसे आदेश देने के अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करेगा और उस व्यक्ति को मांग पर उसकी एक प्रति प्रदान करेगा जब तक कि किसी भी मामले में पासपोर्ट प्राधिकारी की राय में, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के किसी भी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सामान्य जनता के हित में ऐसी प्रति प्रदान करना हित में नहीं होगा।"

इसी तरह, 1967 के अधिनियम की धारा 6 पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों से इनकार के प्रावधान से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"6. पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेजों आदि से इनकार-(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, पासपोर्ट प्राधिकारी धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत किसी भी विदेशी देश का दौरा करने के लिए पृष्ठांकन करने से इनकार करेगा निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर, और किसी अन्य आधार पर नहीं, अर्थात्:-

(क) कि आवेदक ऐसे देश में भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न हो सकता है, या होने की संभावना है;

(ख) कि ऐसे देश में आवेदक की उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है, या होने की संभावना है;

(ग) कि ऐसे देश में आवेदक की उपस्थिति भारत के उस या किसी अन्य देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, या करने की संभावना है,

(घ) कि केंद्र सरकार की राय में ऐसे देश में आवेदक की उपस्थिति सार्वजनिक हित में नहीं है।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, पासपोर्ट प्राधिकारी धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के तहत किसी भी विदेशी देश का दौरा करने के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर, और किसी अन्य आधार पर नहीं, इनकार करेगा, अर्थात्: -

(क) कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) कि आवेदक भारत के बाहर भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न हो सकता है, या होने की संभावना है;

(ग) कि भारत से आवेदक का प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है, या होने की संभावना है;

(घ) कि भारत के बाहर आवेदक की उपस्थिति भारत के किसी भी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, या करने की संभावना है;

(ङ) कि आवेदक को, उसके आवेदन की तारीख से ठीक पहले के पांच साल की अवधि के दौरान किसी भी समय, भारत में किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है और उसके संबंध में उसे कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है;

(च) कि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है;

(छ) कि आवेदक की उपस्थिति के लिए एक वारंट या समन, या आवेदक की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है या ऐसे किसी भी न्यायालय द्वारा भारत से आवेदक के प्रस्थान को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है;



(ज) कि आवेदक को प्रत्यावर्तित किया गया है और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति नहीं की है;

(झ) कि केंद्र सरकार की राय में आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।"

19. उपरोक्त धाराओं के सीधे पढ़ने से यह स्पष्ट होगा कि आवेदन प्राप्त होने पर, पासपोर्ट प्राधिकारी को ऐसी जांच करने का अधिकार है जिसे वे पासपोर्ट जारी करने से पहले आवश्यक समझ सकते हैं। ऐसी जांच करने की शक्ति के कारण ही, पासपोर्ट अधिकारी उस व्यक्ति के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मांग सकता है जिसने पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया है। पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी जांच का उद्देश्य स्वयं को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए या अस्वीकृत किए जाने चाहिए। किसी भी मामले में, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के जारी करने पर निर्णय केवल पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा ही लिया जाना है और ऐसा निर्णय लेने के लिए वे जांच रिपोर्ट को ध्यान में रख सकते हैं। केवल इसलिए कि प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रतिकूल है, पासपोर्ट प्राधिकारी पासपोर्ट जारी करने पर अपने स्वयं के निर्णय से भिन्न नहीं हो सकता है, न ही वे रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों पर विचार किए बिना इसे अस्वीकृत कर सकते हैं।

20. प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट स्वयं में किसी नागरिक को पासपोर्ट रखने के उसके कानूनी अधिकार से अधिकार से वंचित नहीं करती है। यह पासपोर्ट प्राधिकारी पर निर्भर करता है कि वह सत्यापन रिपोर्ट में कथित व्यक्ति के तथ्यों/पूर्ववृत्त पर विचार करे, जिसने पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया है, यह तय करने के लिए कि उसे पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए या अस्वीकृत किया जाना चाहिए। पासपोर्ट प्राधिकारी प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट से बाध्य नहीं है।

21. रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि किस आधार पर प्रतिकूल पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया गया था कि क्या याचिकाकर्ता एक भारतीय नागरिक है या नहीं।

22. प्रतिवादियों की चुनौतीप्राप्त कार्यवाई को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसे रद्द किया जाना है। हालांकि, प्रतिवादियों के लिए यह खुला है कि यदि उसके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है तो वे कानून में अनुमेय उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करें।

23. उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटान किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण के आवेदन का तुरंत निपटान करें, बिना किसी और देरी के अधिमानतः आठ सप्ताह की अवधि के भीतर।

24. सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हैं) भी निपटाए जाते हैं।

25. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनूप कुमार ढंड), जे

करन / 45

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

